



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 27 मई, 2006/6 ज्युलै, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 27 मई, 2006

संख्या एल० एल० आर० डी(६)-16/2006-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 25-5-2006 को प्रस्थापित

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश संख्यांक 2) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव ।

2006 का अध्यादेश संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अध्यादेश, 2006 है।

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 28 धारा 28 की उप-धारा (1) में, विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक का संशोधन। प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु धारा 12 की उप-धारा (4) के अधीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की किसी अतिरिक्त रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन वर्ष की एक तिमाही के अवसान के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्योहारी द्वारा किया जा सकेगा और जहाँ निर्धारण प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि कर अवधि की विवरणियाँ सही और पूर्ण हैं, तो वह विहित रीति में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्योहारी को आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अतिरिक्त रकम का प्रतिदाय करेगा या आगामी कर अवधि के लिए उसका अग्रनयन अनुज्ञात करेगा :

परन्तु यह और कि जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्योहारी के विरुद्ध कोई अन्वेषण, संवीक्षा, निरीक्षण या लेखा परीक्षा या अन्य कोई जांच लम्बित है और प्रतिदाय मंजूर करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि ऐसे प्रतिदाय के संदाय से ऐसे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, जो ऐसे अन्वेषण, संवीक्षा, निरीक्षण या लेखा परीक्षा या अन्य जांच की समाप्ति पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्योहारी से देय हो सकेगा, तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्योहारी को प्रतिदत्त की जाने वाली

रकम के बराबर प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने के अर्ध्यधीन, या तो अतिरिक्त आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम का प्रतिदाय कर सकेगा या प्रतिदाय को कार्यवाहियों की समाप्ति तक रोक सकेगा।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।

प्रधान सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला :

तारीख.....

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 2 of 2006.

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2006**

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2006.

Short title

12 of 2005

2. In section 28 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, in sub-section (1), of the existing first proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

Amend-
ment of
Section
28.

“Provided that an application for refund of any excess amount of input tax credit under sub-section (4) of section 12, may be made by a registered dealer after the expiry of a quarter of the year and where the Assessing Authority finds that the returns for the tax period are correct and complete, it shall in the prescribed manner refund to such registered dealer the excess amount of input tax credit or allow it to be carried forward to the next tax period :

Provided further that where any investigation, scrutiny, inspection or audit or other enquiry is pending against the registered dealer, and the officer authorised to sanction the refund is of the opinion that the payment of such refund is likely to adversely affect the revenue which may become due from such registered dealer at the conclusion of such investigation, scrutiny, inspection or audit or other enquiry, he may, for reasons to be recorded in writing, either refund the amount of excess input tax credit subject to furnishing of a security equal to the amount to be refunded to such registered dealer or withhold the refund till such time the proceedings are concluded;”.

